श्री विद्याचरण शुक्ल : पांच मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : पांच मिनट का है। स्टेटमेंट करवा देते हैं, पांच मिनट में, पता लग जाएगा कि क्लैरीफिकेशन के लिए कोई चीज है भी कि नहीं। तो पांच मिनट बीच में स्टेटमेंट करवा देते हैं। चलिए मंत्री जी आप फटाफट पढ़िए अपना स्टेटमेंट। बांटिए जल्दी से स्टेटमेंट।

STATEMENT BY MINISTER

Talks between India and Nepal on Water Resources Development

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपसभाध्यक्षा जी,

यद्यपि भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन विकास में सहयोग के बारे में बातचीत काफी समय पहले से की जाती रही है लेकिन नेपाल में लोकतन्त्र की बहाली के बाद से इस क्षेत्र में नई शुरूआत की गयी। नेपाल के प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1991 में भारत का दौरा किया तथा हमारे प्रधान मंत्री ने अक्तूबर, 1992 में नेपाल की यात्रा की। जल संसाधनों के बारे में अधिकारियों के स्तर पर 1971 से तथा जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में उप आयोग स्तर पर 1988 से बातचीत की जा रही थी। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की यात्राओं के समय हुए समझौते में करनाली, पंचेश्वर और सप्त कोसी बहु प्रयोजनी परियोजनाओं, मध्यम परियोजनाओं, बाढ़ तटबन्ध एंव बाढ़ पूर्वानुमान योजनाओं के बारे में निर्णय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों देशों के बीच टनकपुर परियोजना तथा सीमाओं पर विद्युत के आदान प्रदान के बारे में भी निर्णय लिये गये। प्रधान मंत्री की अक्तूबर, 1992 में हुई बैठक के दौरान क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर सहमति हुई थी। ये विभिन्न कार्यकलाप इस वर्ष 1993 के दौरान पूरे किए जाने थे। ये कार्य विभिन्न कारणों की वजह से पूरे नहीं किये जा सके।

मन्त्री स्तरीय बातचीत के लिए नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान मैं वहां के नरेश, प्रधान मन्त्री एवं अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से मिला। मैं इस बात से प्रोत्साहित हुआ कि आपसी फायदे के लिए नेपाल की ओर से जल संसाधनों के विकास में रूचि दिखायी गयी। मैंने नई परियोजनाओं पर खास प्रगति न होने के मूल कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया और सुझाव दिया कि इनका पता लगाया जाये ताकि उपचारात्मक उपाय किये जा सकें। नेपाल के साथ हमारी बातचीत के दौरान हम अपने प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के समय सहमत विभिन्न परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाने के वास्ते उन्हें राजी करने में सफल रहे ताकि शीघ्र अनुपालना की जा सके। कार्य योजना के सहमत नये समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, आगामी वर्ष 1994 में विभिन्न कार्यकलाप शुरू किये जाने का कार्यक्रम है और नेपाल की ओर से मिलने वाले सहयोग के आधार पर अगले लगभग दो वर्ष में दोनों पक्षों द्वारा ये कार्य किये जा सकते हैं। नेपाल और भारत में समस्याएं एक जैसी हैं। उत्पादित विद्युत की इन दोनों देशों के विकास कार्यों में उपयोग के लिए बहुत ही आवश्यकता है। जलाशय परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन के अलावा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी लाभ भी प्रदान करती हैं। यह सुझाव दिया गया कि जिन परियोजनाओं पर समझौता होगा उनके क्रियान्वयन में भारतीय वित्तीय संस्थाओं और यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं के वास्ते द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से अपेक्षित धन जुटाने के लिए हम संयुक्त प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि जल विद्युत के विकास के लिए प्राईवेट क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकार किया जाये।

नदी जल जिसे दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए संरक्षित किया जा सकता है, बाढ़ के समय विस्तृत पैमाने पर तबाही भी करता है। इस वर्ष कोसी नदी में बाढ़ के कारण हुई ऐसी तबाही हमने देखी और इससे नेपाल में कोसी उच्च बांध परियोजना के निर्माण की आवश्यकता के बारे में भारत और नेपाल दोनों को चिन्ता हुई। कोसी परियोजना पर सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य हमारे द्वारा शुरू करने पर

प्रारंभ में उनका उत्तर भी प्रेरक नहीं रहा, परन्तु इस परियोजना पर मई, 1994 में बातचीत शुरू करने के लिए उन्हें राजी कर लिया गया है ताकि व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा सके। भारत ने पंचेश्वर परियोजना पर काफी अच्छी प्रगति की है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए उसे नेपाल के सहयोग की आशा है।

नई परियोजनाओं को शुरू करने में मुख्य कठिनाई इन परियोजनाओं की लागत और उनसे होने वाले लाभों के बारे में समझौते की कमी है। सुझाव दिया गया कि दोनों देशों को मिलकर कार्य करना चाहिए तथा विभिन्न घटकों के बीच परियोजना की लागत बांटने एवं आपसी लाभों के आकलन करने की पद्धति को अंतिम रूप देना चाहिए।

अलग-अलग ग्रुपों द्वारा देख-रेख की जा रही विभिन्न परियोजनाओं में कार्य की शीघ्र प्रगति के लिए नेपाल पक्ष कार्यकलापों की त्रैमासिक रूप से मानीटरी करने के लिए एवं इन दोनों सरकारों के सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा वर्ष में दो बार समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया है। दल की अध्यक्षता इन दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा की जायेगी तथा इसमें उर्जा, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।

नेपाल सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री श्री एल. पी. धिमिरे को, दोनों देशों के सुविधाजनक समय पर भारत की यात्रा करने के लिए आमन्त्रित किया गया। यह आमन्त्रण उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया है और हम निकट भविष्य में उनसे एवं उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मण्डल से भेंट करने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि इस दिशा में और अधिक प्रगति की जा सके।

Short duration discussion on J.P.C. Report on irregularities in securities and Banking transactions—Contd.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब हम फिर से कल से चल रही अल्पकालिक चर्चा शुरू करेंगे श्री टी० जी० वेंकटरामन्।

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu) : Madam, for the last two days a discussion is going on about the considered opinion of the JPC. Many hon. Members in this House have put forward their considered opinions. Madam, this securities scam has rocked this country. According to the JPC Report it started from the year 1980. It has come to surface only in 1991-92. These securities transactions of varied types have been done with a view to siphon off the funds of banks. The Report also says that the bank officials were cooperative. It has been brought to light right from the lowest cadre to the highest cadre. All of them have been very cooperative because they had their own dividends. Through various types of transactions, the securities have been siphoned off and bank funds have been defrauded.

Now there are varied versions about the total amount involved in the securities scam. According to the Janakiraman Committee Report, it is Rs. 4000 crores odd. According to the Custodian, it is Rs. 3,650 crores. The CBI says it is Rs. 8,383 crores. Therefore, the amount is more than Rs. 8,383 crores. This amount has been siphoned off from the banks and the public sector undertakings. But we have not been able to find out where it has been hidden and who is having it. We have not been able to trace it out and every one is trying to shove the responsibility on to the other. We have heard arguments from both the sides. We have been sitting here like judges. Majority of the Members in the JPC were from the treasury benches. Members from various other parties also participated. We have heard arguments saying that people sitting here should be pardoned and they should be given another chance. But they are not able to understand and they do not want to see it. The Report is unanimous. There are one or two dissensions. They have a separate view point. They have given their viewpoint to show as to where they differ. There are no two opinions on that aspect also. But now the treasury benches want to argue